सच्चाई के दम पर
जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769 www.swarajindianews.com swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹ 02

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

कानपुर, गुरुवार, 03 जुलाई, 2025
वर्षः 02, अंकः 180, पृष्ठः 8+4

इनसाइड 338 दिन बाद अवनीश दीक्षित जेल से रिहा... » Pg 04

परमाणु बम पर आर-पार के मूड में ईरान

» Pg 12

अपना मोर्चा के शंखनाद से घबराए अनुप्रिया और आशीष पटेल

बगावत से मचा सियासी भूचाल

लखनऊ में सोनेलाल पटेल की जयंती पर शक्ति प्रदर्शन, लेकिन भीतरखाने पार्टी में गहराता असंतोष

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अपना दल (एस) के भीतर मची उठापटक नए मोड़ पर पहुंच गई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपना मोर्चा नामक नए संगठन के गठन के बाद से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति, राज्य मंत्री आशीष पटेल की सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं यह दर्शा रही हैं कि अंदरखाने हालात सामान्य नहीं हैं।

बुधवार को लखनऊ के चारबाग स्थित रवीन्द्रालय सभागार में यशकाय डॉ. सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित जन स्वाभिमान दिवस समारोह में अपना दल (एस) ने अपनी ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मंच से नेताओं की जुबान में जो तल्खी दिखी, उसने साफ कर दिया कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विश्वास जताया कि पार्टी एनडीए के साथ मिलकर 2022 से बेहतर प्रदर्शन करेगी। साथ ही ओबीसी मंत्रालय गठन की मांग को भी प्रमुखता से उठाया।

विरोधियों पर बरसे आशीष पटेल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि जो सोचते हैं कि पीछे से वार कर अपना दल को खत्म कर देंगे, वो भ्रम में हैं। हमें डराना आसान नहीं है। उन्होंने बिना नाम लिए अपना दल से अलग हुए नेताओं को आड़े हाथों लिया और यह भी कहा कि उन्हें किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश हो सकती है। वहीं, अनुप्रिया बोलीं-साजिशें ताकतवर लोगों के खिलाफ होती हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने पति का समर्थन करते हुए कहा कि सिर्फ ताकतवर और ईमानदार लोगों के खिलाफ ही साजिशें होती हैं। अपना दल की बढ़ती लोकप्रियता से लोगों को घबराहट हो रही है।

बगावत के बीच फेरबदल

राष्ट्रीय सचिव माता बदल तिवारी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बलरामपुर में बसपा और सपा से जुड़े कई नेता अपने समथर्कों के साथ अपना दल (एस) में शामिल हुए। लेकिन सूत्रों की मानें तो पाटीज़् के भीतर से कई विधायक अपना मोचाज़् के संपकज़् में हैं और जल्द बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है।

सत्ता में होते हुए भी डगमगाते आत्मविश्वास के संकेत हैं!

विश्लेषक मानते हैं कि जिस तरह से दोनों शीर्ष नेता अनुप्रिया और आशीष पटेल साजिश, जेल, पद त्याग जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वह महज़ मंचीय आक्रोश नहीं, बल्कि पार्टी में अंदरूनी असंतोष की स्वीकारोक्ति है। अपना दल (एस) की ताकत जातीय समीकरणों और वंचित वर्ग के समर्थन पर टिकी रही है। अगर यही वर्ग विभाजित हो गया तो पार्टी के लिए 2027 की राह कठिन हो सकती है।

यूपी सरकार में कौन है आशीष पटेल का दुश्मन?

अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर पार्टी ने लखनऊ में कार्यक्रम में कहा कि पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है। आशीष पटेल ने यूपी सरकार पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। आशीष पटेल ने एक बार फिर बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना विभाग पर निशाना साधा। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि 1700 करोड़ के बजट पर चलने वाली मीडिया नहीं दिखती है। हमारी कोई खबर और इसी बजट से चलाया जाता है। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है।

प्राकृतिक आपदा — 56 लोग अभी लापता, 370 को सुरक्षित बचाया गया

बादल फटने के बाद से अब तक 19 की मौत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। मंडी जिले में लापता लोग 34 से बढ़कर 56 हो गए हैं। इनमें सर्वाधिक 46 लोग सराज क्षेत्र के हैं। थुनाग में आठ, गोहर में छह लोगों की मौत, करसोग में एक की मौत, कांगड़ा में दो, नादौन और जोगिंद्रनगर में एक-एक जान गई है। 370 लोगों को रेस्क्यू

किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रेस्क्यू और आपदा राहत के लिए वायुसेना की मदद मांगी है। सराज के थुनाग में 16, पखैरर में 18, जरोल में 7, चिऊणी में 4 और पांडवशीला में एक व्यक्ति लापता है। गोहर उपमंडल के स्यांज और बाड़ा परवाड़ा में छह लोगों की मौत हुई हैं जबकि आठ लापता हैं। करसोग उपमंडल में एक की मौत हुई है। जबकि दो लापता हैं। बादल फटने और भूस्खलन के चलते थुनाग और जंजैहली उपमंडल में सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। कई क्षेत्रों में एनडीआरएफ एसडीआरएफऔर प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हैं।

सोमवार रात को बादल फटने और भारी बारिश-भूस्खलन से प्रदेश में 100 से अधिक सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मंडी में 148 घर, 104 गोशालाएं, 14 पुल ध्वस्त हो गए हैं। 31 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रदेश में 918 बिजली ट्रांसफार्मर व 683 पेयजल योजनाएं ठप हैं। कुल्लू की बंजार घाटी में फंसे करीब 250 सैलानी सुरिक्षत निकाल लिए गए हैं।

प्रदेश में एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 9 जुलाई तक भारी बारिश जारी रहने का अलर्ट है। 3 व 4 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 5 से 9 जुलाई तक कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। नदी-नालों, भूस्खलन के प्रति संवेदनशील स्थलों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही मौसम की स्थिति के अनुसार अपनी यात्रा तय करने को कहा गया है।

लकड़ी माफिया के लिए स्वराज इंडिया की खबर बनी कहर

» पेड़ कटाई प्रकरण में केस दर्ज, मौके पर भेजी गई वन विभाग की जांच टीम

» डीएफओ बोलीं : अवैध कटाई पर जीरो टॉलरेंस, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी

» खबर प्रकाशित होने के 24 घंटे के भीतर देखने को मिली बड़ी कार्यवाही

स्वराज इंडिया
Swaraj India
02 Jul 2025 - Page 3

हरे पेड़ों का कत्लेआम, लकड़ी माफिया फरार

प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। चौबेपुर ब्लॉक अंतर्गत राय गोपालपुर ग्राम पंचायत के गोविंदेपुर गांव में हरे-भरे पेड़ों की बेरहमी से कटाई कर दी गई। पिपरियन निवासी अरविंद नामक लकड़ी माफिया पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मनोज सविता के आम के बाग में दर्जनों हरे पेड़ अवैध रूप से काट दिए।

» राय गोपालपुर पंचायत के आम के बाग में दर्जनों पेड़ काटे, ग्रामीणों से की गई अभद्रता

» वन विभाग हरकत में, डीएफओ बोलीं मामले में होगी सख्त कार्रवाई, दर्ज होगी एफआईआर

जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तो माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ अभद्रता और धमकियां दीं। इस घटना की सूचना जैसे ही क्षेत्रीय पत्रकारों तक पहुँची, वे मौके पर पहुंचे लेकिन अरविंद और उसके साथी तब तक फरार हो चुके थे।

पत्रकारों ने तुरंत टिकरा पुलिस चौकी को सूचना दी, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।सूत्रों की मानें तो अरविंद एक शातिर लकड़ी तस्कर है, जो लंबे समय से हरे पेड़ों की चोरी कर लकड़ी अवैध रूप से बेचने का धंधा करता आ रहा है।गांव वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस अवैध कारोबार में वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है, जिन्हें नियमित कमीशन दिया जाता है।दैनिक स्वराज इंडिया की टीम ने जब इस मामले पर कानपुर के जिला वन अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और अरविंद के खिलाफ वन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

हलचल
खबर का असर

प्रमुख संवाददाता, दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। राय गोपालपुर पंचायत के गोविंदेपुर गांव में हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में स्वराज इंडिया की खबर के प्रकाशित होते ही प्रशासन हरकत में आ गया। घटना के 24 घंटे के भीतर जिला वन अधिकारी (डीएफओ) दिव्या ने मौके पर टीम भेजकर स्थलीय जांच कराई और मुख्य आरोपी अरविंद के खिलाफ केस दर्ज कर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी।

बीते दिन गांव के मनोज सविता के आम के बाग में दर्जनों पेड़ों को लकड़ी माफिया अरविंद के द्वारा अवैध रूप से काटा गया था।

जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ अभद्रता और धमकियां दी गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और स्वराज इंडिया की टीम ने इस मामले को प्रमुखता से

जिला वन अधिकारी दिव्या का आधिकारिक बयान

"स्वराज इंडिया में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लिया गया है। अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की जांच के लिए विभागीय अधिकारियों को मौके पर भेजा गया था। वन विभाग की नीति इस पर स्पष्ट है अवैध कटाई पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। दोषियों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा।"

विश्वविद्यालय

यूपी में डिग्री के नाम पर धोखा

आर्यन शर्मा का शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा हमला

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों छात्र कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास न तो ज़रूरी स्किल होती है और न ही नौकरी की दिशा। इस शिक्षा संकट के खिलाफ अब FacultyPaths के संस्थापक आर्यन शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। आर्यन का कहना है कि प्रदेश में छात्रों से लाखों रुपये वसूल कर उन्हें केवल डिग्री थमाई जा रही है, न कि उन्हें जॉब-रेडी बनाया जा रहा है।

» FacultyPaths के फाउंडर ने उठाया एजुकेशन माफिया के खिलाफ झंडा

» डिग्री नहीं, दिशा चाहिए आर्यन शर्मा ने किया भ्रष्ट सिस्टम को बेनकाब

आर्यन ने शिक्षा संस्थानों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, आज भी छात्रों को आउटडेटेड रिज्यूम फॉर्मेट सिखाया जा रहा है (जीपीटी ऐ आई एटीएस फ्रेंडली) रिज्यूम, इंटरव्यू स्किल्स, या लिंक्डइन प्रेजेंस जैसी बुनियादी चीजों की जानकारी तक नहीं दी जा रही। ये संस्थान छात्रों को जॉब मार्केट के लायक नहीं बना रहे।

FacultyPaths की रिपोर्ट में खुलेंगे नाम, होंगे कड़े खुलासे

आर्यन शर्मा ने दावा किया कि उनके पास ऐसे छात्रों की सूची है जिन्हें कॉलेज गए बिना, परीक्षा दिए बिना सिर्फ पैसे देकर डिग्री दे दी गई। उन्होंने इसे सिर्फ अकादमिक असफलता नहीं बल्कि एक करियर स्कैम बताया।

आर्यन ने बताया कि वह इस पूरे सिस्टम पर एक विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें डिग्री बेचने वाले कॉलेजों और उनसे जुड़े लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे।

अब सिर्फ शिकायत नहीं, सबूत और समाधान दोनों लेकर आ रहा हूं।

उन्होंने कहा कि कुछ संस्थान अब सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन बड़े बदलाव के लिए युवाओं को जागरूक होना होगा।

केडीए में धांधलियों पर अफसरों की मौन सहमति !

» केडीए के केयर टेकर अनुभाग में कार्य पहले, टेंडर बाद में का मामला चर्चा का विषय बना

» केडीए पोर्टिको फार सीलिंग और रिकार्ड रूम मरम्मत कार्य पहले ही हो चुका, अब कैसे निकाला गया टेंडर

» केयर टेकर अनुभाग में चल रही बडी धांधली पर चुप्पी साधे अधिकारी

स्वराज इंडिया | कानपुर सिटी | 02 जुलाई, 2025 | 03

केडीए केयर टेकरः कार्य पहले, टेंडर बाद में

» केडीए मुख्यालय के पोर्टिको में फार सीलिंग कार्य और रिकार्ड रूम मरम्मत कार्य पहले ही हो चुका, अब निकाला गया टेंडर

» केडीए के केयर टेकर अनुभाग में चल रही बडी धांधली

कार्य 4 माह पहले करवाया जा चुका है

सफाई सुपरवाइजर बन गया ठेकेदार

केयर टेकर नहीं संभाल पा रहे अतुल राय!

स्वराज इंडिया | कानपुर सिटी | 01 जुलाई, 2025 | 03

पौन घंटे तक लाइट गुल, मोबाइल की रोशनी में चला काम, बड़े-बड़े जेनरेटर निकले बेकार

केडीए में अंधेरा नहीं, भ्रष्टाचार की कालिख!

आवेदक से घूस मांगने पर केडीए लिपिक निलंबित

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। केडीए-कानपुर विकास प्राधिकरण में अफसरों की चुप्पी भ्रष्टाचार को बढावा और संरक्षण दे रही है। प्राधिकरण में धांधलियों की फेहरिस्त बढती जा रही। जांच के नाम पर कमियों और भ्रष्टाचार पर लगातार पर्दा डाला जा रहा है। इससे सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टालरेंस नीति को सीधे सीधे पलीता लग रहा है। केयर टेकर में बिना टेंडर के लाखों रूपयों के कार्य कराए जाने का मामला पकडा गया है। अब इसमें जिम्मेदार अधिकारी बयान देने से बच रहे हैं।

विभागीय सूत्रों का दावा है कि केयर टेकर अनुभाग में हर माह लाखों रूपयों के भुगतान विभिन्न मदों पर किए जा रहे हैं लेकिन सरकारी नियमों को दरकिनार कर चहेते ठेकेदारों और डमी फर्मो के माध्यम से भुगतान सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। ताजा इनपुट के मुताबिक केडीए मुख्यालय के पोर्टिको में फाल सीलिंग लगाने का कार्य 3 माह पूर्व हो चुका है लेकिन 2 जुलाई 2025 को 2 लाख 45 हजार रूपए का टेंडर निकाल दिया गया। वहीं, पोर्टिको की मरम्मत के नाम पर सिर्फ फॉल–सीलिंग टांग दी गई हैं, जब कि छत की सरिया भी दिख रही थीं उनपर प्लास्टर करना भी जरूरी नहीं समझा गया। इसी तरह से केडीए के रिकार्ड रूम की रंगाई पुताई और मरम्मत के नाम पर 2 लाख 99 हजार रूपए का टेंडर निकाला गया। विभागीय सूत्रों का दावा है कि यह कार्य भी पहले ही हो चुका है। इस तरह से केयर टेकर में मरम्मत और आपूर्ति के नाम पर लगातार फर्जी फाइलें बनाकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। हालांकि, यह प्रकरण शासन तक पहुंचा है। केडीए की लापरवाह और भ्रष्ट कार्यशैली की तमाम शिकायतें पहले ही शासन में लंबित चल रहे हैं, ऐसे में आए दिन आ रहे प्रकरण कई सवाल खडे कर रहे हैं।

इस मामले में वीसी मदन सिंह गर्ब्याल से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन बात नहीं हो सकी। वहीं, सचिव अभय पांडेय मीटिंग में व्यस्त होने का हवाला दिया।

अनुभवहीन इंजीनियर डुबो रहे लुटिया

केडीए में कई असिस्टेंट इंजीनियरों की तैनाती हुई है। इंजीनियरों की कमी के कारण उनसे महत्वपूर्ण सीधे कार्य लिए जा रहे हैं। इससे केडीए के कामकाज में नाकारात्मक प्रभाव भी पडा है। केयर टेकर प्रभारी के तौर पर जब से एई अतुल राय की तैनाती की गई है तब से कामकाज में पारदर्शिता नहीं है। मनचाहे ढंग से फाइलों को बनाकर कार्य कराए जाने की शिकायतें आ रही हैं और धांधली की आशंका बनी हुई है।

पहले भी हो चुका डीजल घोटाला कांड

केयर टेकर अनुभाग में पहले भी डीजल घोटाला कांड हो चुका है। इसमें बिना जेनसेट चले ही डीजल खरीद के नाम पर लाखों रूपयों का भुगतान ले लिया गया था।

इसकी शिकायत तत्कालीन कर्मचारी नेता बचाउ सिंह सहित अन्य ने की थी इसपर कई इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई थी। कई वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए प्रकरण अभी भी शासन में लंबित है। ऐसे में केडीए में एकबार फिर भ्रष्टाचार का खेल सजाया जा रहा है।

338 दिन बाद अवनीश दीक्षित जेल से रिहा

28 जुलाई को भेजा था जेल,21 मुकदमे थे दर्ज, इनमें मिली जमानत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। अवनीश को गैंगस्टर एक्ट और पीएफ घोटाले जैसे पांच अपराधिक मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बाकी 16 में उसे सेशन कोर्ट से सुनवाई होने के बाद जमानत मिल गई थी।

कानपुर में पिछले साल 28 जुलाई से जेल में बंद प्रेसक्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित 339 दिन बाद बुधवार रात जेल से रिहा हो गए। सिविल लाइंस में मैरी एंड मैरीमैन कंपाउंड की करोड़ों की जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में कानपुर तहसील के लेखपाल विपिन कुमार और कंपाउंड निवासी सैमुअल गुरुदेव ने अवनीश समेत अन्य पर कब्जे, डकैती की दो एफआईआर दर्ज कराई थी।

अवनीश दीक्षित के जेल में रहते हुए पुलिस ने उसके पुराने आपराधिक मामलों की भी जांच की और एक के बाद एक 21 मामले दर्ज किए गए, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के निर्देश पर अवनीश को गैंग लीडर बनाते हुए पहला इंटर जोनल गैंग घोषित किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि देर रात लगभग 10 बजे अवनीश जेल से रिहा हो गया।

सभी मामलों में लग चुकी है चार्जशीट

अवनीश ने जेल गेट से निकलते-निकलते बाबा आनंदेश्वर को धन्यवाद दिया। इधर, अवनीश के निकलने के बाद किदवईनगर पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस ने वहां पर फिर से अवनीश को लेकर पूछताछ की। एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार ने बताया कि अवनीश दीक्षित के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में चार्जशीट लग चुकी है। सभी आपराधिक मामलों में उसकी जमानत हो गई, जिसके बाद उसकी रिहाई हुई है।

पांच में हाईकोर्ट और 16 में सेशन कोर्ट से जमानत

अवनीश को गैंगस्टर एक्ट और पीएफ घोटाले जैसे पांच अपराधिक मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बाकी 16 में उसे सेशन कोर्ट से सुनवाई होने के बाद जमानत मिल गई थी। बुधवार को हाईकोर्ट से उसे पीएफ घोटाले में जमानत मिली तो उसे सलाखों से भी आजादी मिल गई।

जमानतगीर न मिलने से रिहा होने में लगा वक्त

कानून के जानकारों के मुताबिक अवनीश को मई में ही बाहर आ जाना चाहिए था मगर जिन मामलों में उसकी जमानत हुई थी। उसके जमानतदारों ने एक-एक कर हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिए। कई जमानतदारों ने अपनी जमानतें वापस ले ली। नए जमानतदारों को कोर्ट के सामने लाने में वक्त लग गया।,

बिकरू कांड के शहीदों को शिवराजपुर पुलिस ने दी श्रद्धांजलि

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। बिकरू कांड की पांचवीं बरसी पर बुधवार को शिवराजपुर थाना परिसर में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपस्थित पुलिसकर्मियों ने पुष्प अर्पित कर अपने साथियों को याद किया और मोमबत्ती जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

थानाध्यक्ष ने शहीदों की तस्वीरों के समक्ष मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 की वह रात पुलिस इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी। शहीद हुए पुलिसकर्मी आज भी हम सबकी प्रेरणा हैं।

श्रद्धांजलि सभा में उपनिरीक्षक अश्विनी सिंह, विनोद दिवाकर, शुभम पांडेय, नरेंद्र कुमार, हिमांशु सिंह, सुनील रिज़वी, शिवम कुमार,हेड कांस्टेबल अफरोज खान, अभय तिवारी समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

यह आठ पुलिस कर्मी हुए थे शहीद

सीओ देवेंद्र मिश्र	कांस्टेबल राहुल
इंस्पेक्टर महेश यादव	कांस्टेबल बबलू
सब-इंस्पेक्टर अनूप सिंह	कांस्टेबल जितेंद्र
कांस्टेबल सुल्तान सिंह	ड्राइवर जयबाज सिंह

परिचय बैठक में तहसीलदार के रवैए पर भड़के वकील, किया गया बहिष्कार

» **सहयोगात्मक व्यवहार न होने का लगाया आरोप**

» **नवनियुक्त तहसीलदार ने हाल ही में संभाला है चार्ज**

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। तहसील सभागार में बुधवार को आयोजित परिचय बैठक उस वक्त हंगामे में बदल गई जब अधिवक्ताओं ने नवनियुक्त तहसीलदार अभिनव चंद्र के रवैए को लेकर नाराज़गी जताई और बैठक का बहिष्कार कर नारेबाज़ी शुरू कर दी।

वकीलों का आरोप है कि बैठक की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी बात रख रहे थे, लेकिन तहसीलदार का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं रहा। इसी कारण अधिवक्ताओं ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। अधिवक्ता महेंद्र कुशवाहा,आलोक मिश्रा, अमित श्रीवास्तव और विनय गौतम ने बताया कि तहसील प्रशासन से सम्मानजनक संवाद की उम्मीद थी, लेकिन जब रवैया ही सही नहीं रहा तो बैठक में बने रहना मुनासिब नहीं था। संगठन इस मसले पर आगे की रणनीति तय करने के लिए अलग बैठक करेगा। उधर तहसीलदार अभिनव चंद्र ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि बैठक में ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। भविष्य में फिर से बैठक बुलाकर संवाद की कोशिश की जाएगी।

स्वराज इंडिया
www.www.swarajindianews.com.com
वैचारिक मंच

सम्पादकीय

जिंदगी बचाने को पहल करे एनएचएआई

निस्संदेह, हाल के वर्षों में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस–वे आदि का आशातीत विस्तार हुआ है। सड़कों के नेटवर्क सुधार से उपभोक्ताओं के समय व धन की बचत हुई है तो उद्योग–व्यापार को भी गति मिली है। लेकिन इससे जुड़ी तमाम विसंगतियां भी सामने आई हैं। सड़कों के त्रुटिपूर्ण डिजाइन व निर्माण में चूक को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। पिछले हफ्ते मध्यप्रदेश में लगातार 40 घंटे लगे जाम से जहां हजारों लोगों को घंटों परेशान होना पड़ा, वहीं जाम में फंसकर तीन लोगों की मौत हुई है। निश्चय ही यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको लेकर शासन–प्रशासन के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई को गंभीरता से लेना चाहिए। उन तमाम आशंकाओं को टालना चाहिए जो भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति के कारक बन सकते हैं। बहरहाल, मध्यप्रदेश की घटना को लेकर एनएचएआई की आलोचना की जा रही है। इस घटना के बारे में एनएचएआई के एक अधिकारी की संवेदनहीन टिप्पणी को लेकर भी सवाल उठे हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी एनएचएआई के रुख को कठोर और संवेदनहीन बताया है, जो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने वाला है। दरअसल, एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एनएचएआई को दोषपूर्ण और देर से सड़क निर्माण के लिये फटकार लगायी है, जिसके कारण आगरा–मुबई राष्ट्रीय राजमार्ग के इंदौर–देवास खंड में जाम लग गया था। बताते हैं कि एनएचएआई के कानूनी सलाहकार ने इस बाबत संवेदनहीन टिप्पणी की कि लोग बिना किसी काम के घर से इतनी जल्दी क्यों निकलते हैं? इस टिप्पणी ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। निश्चित रूप से इस दुर्घटना और हजारों लोगों के घंटों जाम में फंसे रहने के मामले में जहां एनएचएआई की तरफ से माफी मांगने की जरूरत थी, वहीं उसने दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिये दोष लोगों पर लगाते हुए असंवेदनशील बयान दे डाला। जिसके खिलाफ तल्ख प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। यही प्रतिक्रिया अदालत की टिप्पणी में भी झलकती है। इसमें दो राय नहीं कि अकसर बड़ी सड़कों और राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के दौरान अंतहीन असुविधा भारतीय यात्रियों के लिए रोजमर्रा के अनुभव हैं। अधिकांश साइटों पर निर्माण से जुड़ी, यात्रियों के अनुकूल सर्वोत्तम परंपराओं को अपनाना और यातायात में व्यवधान को कम से कम करना सुनिश्चित नहीं किया जाता है। निस्संदेह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सक्रियता व प्रतिबद्धता की अकसर सराहना होती रहती है। वे सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों को बढ़ाने को लेकर लगातार अभियान चलाते भी रहते हैं। हालांकि, वे भी मानते रहे हैं कि अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। निस्संदेह, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निरंतर यातायात को सुगम मानकों के अनुरूप बनाने के लिये प्रयासरत रहता भी है।

निश्चित रूप से स्थलों की स्थिति और भूमि अधिग्रहण के तमाम विवाद भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम राजमार्गों की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर किया जाना होना चाहिए। दरअसल, योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर निर्माण फर्मों और ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है। जिसमें व्यापक अनुभव, क्षमता और नैतिकता जैसे कारक मिलकर भूमिका निभाते हैं। निस्संदेह, काम की गुणवत्ता समस्याओं के समाधान में मददगार साबित हो सकती है।

एक साल बाद आपराधिक कानूनों की दिशा-दशा

केपी सिंह

अब समय आ गया है कि नए आपराधिक कानूनों की पहली समीक्षा की जाए ताकि मसौदा तैयार करने में हुई गलतियों को सुधारा जा सके, खामियों को दूर किया जा सके, कमियों की भरपाई की जा सके और लोगों की वास्तविक चिंताओं को खुले मन से स्वीकार करके कानूनों में आवश्यक फेरबदल किया जाए, जिससे इन कानूनों की उपयोगिता और बढ़ सके। तीन नये आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 को इस उम्मीद के साथ लागू किए गए थे कि भारत में ब्रिटिश काल से चली आ रही आपराधिक न्याय प्रणाली नागरिकों को न्याय प्रदान करने और सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी देने वाली एक जन-केन्द्रित, प्रगतिशील, उद्देश्यपूर्ण एवं सक्षम संस्था के रूप में बदल जाएगी। यद्यपि किसी कानून के लागू होने के बाद एक वर्ष का समय लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इसकी सफलता या विफलता के बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, तथापि यह समय कानून के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं और अवरोधों की पहचान करने के लिए पर्याप्त संकेत छोड़ जाता है।

नए कानूनों के लागू होने से पहले, कई कानून विशेषज्ञों ने उनकी उपयोगिता और व्यावहारिकता के बारे में आशंका व्यक्त की थी। यह सराहनीय है कि न्याय प्रणाली की सभी शाखाओं ने धारा–संख्या और उसमें निहित प्रावधानों में किए गए बदलावों को अच्छी तरह से स्वीकार और अंगीकार किया है। पहले दिन से ही उन्हें बिना किसी समस्या के व्यवहार में लाना शुरू कर दिया है। पूरे देश में नए कानूनों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की जा रही है और उनकी जांच की जा रही है। ऐसा केवल व्यापक पैमाने पर चलाए गए प्रशिक्षण अभियान के कारण ही सम्भव हो पाया है, जिसकी परिकल्पना और योजना गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी, और जिसे सभी हितधारकों द्वारा उत्साहपूर्वक अपनाया गया है। यहां तक कि विधि–विद्यालयों ने भी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में हुए इन बदलावों को बिना किसी कठिनाई के आत्मसात कर लिया है।

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को नए कानूनों में सबसे अधिक वरीयता देकर यह संदेश दिया गया है कि सरकार महिलाओं और अवयस्कों की सुरक्षा

और संरक्षण के प्रति संवेदनशील है। पुलिस ने इन प्रावधानों का बखूबी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त, सज़ा के प्रावधानों का अपराध की संगीनता के अनुसार सरलीकरण करके दण्ड–विधान को सुधारात्मक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, यद्यपि इसके परिणाम कुछ वर्षों बाद ही देखने को मिल सकेंगे।

भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता सबसे महत्वपूर्ण है, और यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 48 के प्रावधानों में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस धारा में, देश के बाहर बैठकर भारत में अपराध को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में अपराधियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 356 के अनुसार आरोपियों की अनुपस्थिति में भी की जा सकती है। हालांकि यह एक कटु सत्य है कि इन धाराओं का आतंकवादियों और गैंगस्टरों के खिलाफ नगण्य प्रयोग किया गया है, फलस्वरूप विदेशों में बैठकर भारत में फिरौती के लिए कॉल करने और आतंकवाद को भड़काने जैसी गतिविधियां रुक नहीं पाई हैं। मुकदमों के अनुसंधान को पारदर्शी और उच्चस्तरीय बनाने के उद्देश्य से प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने के प्रावधान नए कानूनों की विशेषता है। फारेंसिक जांच का दायरा अनुसंधान प्रक्रिया में बढ़ाकर जांच को निष्पक्ष और प्रभावी बनाया गया है। परन्तु यह चिन्ता का विषय है कि अब तक डिजिटलीकरण और फारेंसिक प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की गतिविधियां उतनी रफ्तार से नहीं चल पाई हैं जितनी चलनी चाहिए थी। राज्य सरकारों के सीमित वित्तीय संसाधन इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं।

पिघलते ग्लेशियरों में जल संकट की आहट

ग्लोबल वार्मिंग का असर

ज्ञानेन्द्र रावत

ग्लोबल वॉर्मिंग जैसे कारकों से दुनियाभर में ग्लेशियरों का पिघलना भविष्य में गंभीर जल संकट ला सकता है वहीं इससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। अंटार्कटिका, आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, हिंदूकुश, स्विट्ज़रलैंड या ब्रिटेन- सभी क्षेत्रों में यही स्थिति है। बड़ी चिंता यह कि पर्यावरणीय बदलावों के चलते हिमालयी ग्लेशियर भी चपेट में आ रहे हैं।दुनियाभर के ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर हैं। वे तेजी से पिघल रहे हैं। अगर इनके पिघलने की यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले दशकों में दुनिया एक-एक बूंद पानी को तरस जायेगी। दरअसल, जलवायु की प्रचंड आंधी ग्लेशियरों को निगल रही है। यह केवल बर्फ का पिघलना नहीं है; इससे बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता है, साथ ही यह बुनियादी ढांचे, कृषि उत्पादन और जलीय-स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

वैज्ञानिकों की मानें तो साल 2000 से 2023 के बीच बर्फ के ये पहाड़ यानी ग्लेशियर 650,000 करोड़ टन बर्फ खो चुके हैं। यह सिलसिला जारी है। वेनेजुएला पहला देश है जिसने जलवायु परिवर्तन के असर के चलते अपने सभी ग्लेशियर खो दिये। बीसवीं सदी के मध्य में पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में करीब 400 ग्लेशियर गायब हुए। ग्लेशियरों के पिघलने की स्थिति अंटार्कटिका, आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आल्प्स, रॉकीज़, आइसलैंड, हिंदूकुश, स्विट्ज़रलैंड या ब्रिटेन–सभी जगह लगभग एक जैसी है।

वर्ष 2010 से पहले आर्कटिक और अंटार्कटिका में जो बर्फ की चादर बिछी होती थी, उसमें लाखों वर्ग किमी की कमी हो गयी है। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा हिमखंड ए 23 फिर खिसक रहा है जो महासागरों की धाराओं द्वारा बहाकर लाया गया है और अभी दक्षिण जार्जिया के गर्म जल की ओर बढ़ रहा है। यहां यह टूटकर पिघलने की प्रक्रिया में है। बर्फ के प्राकृतिक रूप से बढ़ने की क्रिया के कारण यह हिमखंड टूटकर अलग हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है जिसने समुद्र का जलस्तर बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है।ग्रीनलैंड में जहां बीते 13 साल में 2,347 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ गायब हो गयी है। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से दुनियाभर में समुद्र के जलस्तर में बदलाव हुआ। मौसम के पैटर्न में भी बदलाव सामने आया है। स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध रोन ग्लेशियर सहित आल्प्स पर्वत श्रृंखला के कई ग्लेशियरों में बर्फ के नीचे सुरंगें और गड्ढे हो गये हैं। तेजी से बढ़ रहे तापमान के कारण अब ग्लेशियर सिर्फ पिघल नहीं रहे हैं, भीतर से खोखले भी हो रहे हैं। हिंदूकुश क्षेत्र के ग्लेशियर से नवम्बर से मार्च तक बर्फ में 23.6 फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई है। यह बीते 23 सालों में सबसे कम है। नतीजन पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। बर्फबारी में यह गिरावट लगातार तीसरे साल दर्ज की गयी है।

जलवायु बदलाव और स्थलाकृति के कारण मध्य हिमालय का एक ग्लेशियर तेजी से खिसक रहा है। ग्लेशियरों की चिंताओं के बीच यह नया संकट है। वैज्ञानिक इस ग्लेशियर का उद्गम भारत में और निकास तिब्बत की ओर मानते हैं। इससे तिब्बत से लेकर धौलीगंगा तक बाढ़ का खतरा बना हुआ है।वह हिमालयी क्षेत्र में 37,465 वर्ग किलोमीटर में फैले कुल 9575 ग्लेशियरों को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। ये ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में जमे ताजे पानी के सबसे बड़े भंडार हैं। इसे विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। एशिया की 10 प्रमुख नदियों को पानी देने वाले इन ग्लेशियरों से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी तीन नदियां विभाजित हुई हैं। कश्मीर में भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यहां भी पानी का संकट है।

सबलू को गोली मारने वाले जीशान व फैजल मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार

पैर में लगी गोली,दोनों पर 25-25 हजार का इनाम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सोमवार रात हिस्ट्रीशीटर व डीटू गैंग के सदस्य सबलू की गर्दन पर गोली मारने में नामजद आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी शाहिद के बहनोई जीशान और उसके भाई फैजल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था।

कानपुर में हिस्ट्रीशीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू को गोली मारने के मामले में शाहिद पिच्चा के बहनोई जीशान कुरैशी और उसके भाई फैजल को पुलिस ने बुधवार देर रात गोविंदपुरी पुल के नीचे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम है। शातिरों के पैर में गोली लगी है। जिन्हें इलाज के लिए हैलट अस्पताल ले जाया गया।चमनगंज निवासी हिस्ट्रीशीटर व डीटू गैंग के सदस्य सबलू बदमाश सोमवार रात दोस्त मो आकिब व शकील के साथ स्कूटी से मोतीझील के पास चाय पीने जा रहा था। दोनों हर्ष नगर पेट्रोल पंप से आगे

पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के पास पहुंचे तभी बाइक सवार बदमाशों ने सबलू पर पिस्टल से फायर कर दिया था।

स्वरूपनगर थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट

गोली उसकी गर्दन में फंस गई और वह गिरकर बेहोश हो गया था। दोनों दोस्त उसे पास के नर्सिंगहोम में भर्ती कराया था। मंगलवार को उसकी ओर से स्वरूप नगर थाने में जेल में बंद शाहिद पिच्चा, उसकी मां, बहनोई जीशान, सनी मौरंग, बिल्डर फिरोज भइया, युसूफ चटनी और तीन अज्ञात पर हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे दोनों

बुधवार रात मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि सबलू को गोली मारने के आरोपी शाहिद पिच्चा का बहनोई जीशान और उसका भाई फैजल गोविंदपुरी स्टेशन जाने के लिए पुल के नीचे झाड़ियों व ट्रैक के पास छिपे हैं। दोनों शहर से बाहर जाने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं।

इस पर सर्विलांस और सेंट्रल जोन के एसीपी स्वरूप नगर इंद्रप्रकाश सिंह के साथ फजलगंज, काकादेव और स्वरूप नगर थानों का फोर्स पहुंच गया।पैर में गोली लगी और दोनों गिर पड़े

घेराबंदी करने के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में जीशान और फैजल के दाएं पैर में गोली लगी और दोनों गिर पड़े। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर

अस्पताल भेज दिया। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि शाहिद के बहनोई जीशान और उसके भाई फैजल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है।

सख्ती: रिन्यू न कराने पर 551 वाहनों के परमिट होंगे निरस्त, संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि स्थायी स्टेज कैरिज, कानपुर नगर बस परमिट, स्कूल बसों, वैन, टेंपो और ऑटो रिक्शा के वे परमिट जिनकी वैधता पांच वर्ष से अधिक समय पूर्व समाप्त हो चुकी है और जिनका नवीनीकरण नहीं कराया गया। उन मामलों पर विचार कर परमिट निरस्तीकरण का निर्णय लिया गया है।

कानपुर में पांच वर्षों में परमिट रिन्यू नहीं कराने वाले 551 वाहन स्वामियों का परमिट निरस्त किए जाएंगे। यह फैसला बुधवार को मंडलायुक्त शिविर कार्यालय में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने, नियमों का सख्ती से पालन कराने व लंबित परमिट प्रकरणों पर चर्चा की गई। जिन रूटों पर अभी सार्वजनिक बसें नहीं चल रही हैं।वहां बस संचालन की संभावना तलाशने और जरूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने, सिटी बसों की संख्या बढ़ाने, 28 सीटर बसों के संचालन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जहां आवश्यकता हो, वहां अनुबंध के माध्यम से बसें चलाने की बात कही गई। प्रवर्तन की कार्रवाई तेज करने के साथ ही उसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया गया। तय हुआ कि जिन वाहन चालकों के तीन या उससे अधिक बार चालान हो चुके हैं।उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में ओवरलोडिंग के कारण सात वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है। परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि स्थायी स्टेज कैरिज, कानपुर नगर बस परमिट, स्कूल बसों, वैन, टेंपो और ऑटो रिक्शा के वे परमिट जिनकी वैधता पांच वर्ष से अधिक समय पूर्व समाप्त हो चुकी है और जिनका नवीनीकरण नहीं कराया गया। उन मामलों पर विचार कर परमिट निरस्तीकरण का निर्णय लिया गया है।अब तक ऐसे 3,430 वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिन बसों का संचालन अंतर्संभागीय मार्गों पर बिना प्रति हस्ताक्षर कराए किया जा रहा था।

BH बॉम्बे हॉस्पिटल
नियर आघू रोड, कानपुर-आगरा हाईवे, अकबरपुर, कानपुर देहात

24 घंटे इमरजेंसी सुविधा
24 घंटे एम्बुलेंस व मेडिकल स्टोर की सुविधा
दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन
हेल्पलाइन नं.: 8355017999, 8858997333
हड्डी के सभी ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी
पित्ताशय की पथरी, फिशर, नासूर
अपेन्डिक्स, प्रोस्टेट, कैंसर की गांठ, भगंदर
हर्निया, हाइड्रोसील, छाती का कैंसर
पेट की चोट व अन्य समस्याएं
बच्चेदानी व अण्डाशय की गांठ
घुटने का प्रत्यारोपण, पाइल्स (बवासीर)

डॉ. सुरेश यादव
डायरेक्टर

बंद फैक्ट्री के सोकपिट में मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी

» थाना रनियां क्षेत्र का मामला

» संदिग्ध हालात में मिली लाश

» एसपी ने मौके पर पहुंचकर की जांच, फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। थाना रनियां क्षेत्र के ग्राम चिटिकपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव की पुरानी और बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर बने शौचालय के सोकपिट गड्ढे में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात स्वयं फोरेंसिक टीम व भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी ने स्थानीय ग्रामीणों से घटना के संबंध में जानकारी ली और पूरे मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए।

घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी अकबरपुर, व अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। फिलहाल मृतक की पहचान व मौत के कारणों की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना – तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छानबीन की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज व स्थानीय संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

ग्रामीणों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस की मौजूदगी से लोग थोड़े आश्वस्त हैं, लेकिन शव की पहचान और मौत के कारण सामने आने तक शंका और चिंता का माहौल बना रहेगा।

अवैध धंधे में लिप्त महिला ने युवक से एक लाख ठगे, लिखाया फर्जी मुकदमा

पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, जांच में जुटी बरौर पुलिस

» धमकाकर युवक और उसकी मां से रकम हड़पी, कोर्ट में झूठा केस दर्ज कराने का आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी एक युवक और उसकी मां ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक महिला ने न सिर्फ उनसे जबरन 1 लाख वसूले, बल्कि बाद में कोर्ट में फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया।

पीड़ित संतोष कुमार और उसकी मां मुन्नी देवी ने बताया कि जलालपुर की रहने वाली पुष्पा, जो वर्तमान में रमईपुर इलाके में (थाना बिधनू) के अंतर्गत रह रही है, लंबे समय से अवैध गतिविधियों में लिप्त है और कई युवकों को झूठे मामलों में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूल चुकी है।

संतोष कुमार का आरोप है कि पुष्पा और उसके पति ने पहले उसे और उसकी मां को धमकाकर बैंक ऑफ बड़ौदा (शाखा डीघ) से 1 लाख रुपये अपने खाते में डलवाए, और फिर झूठे मुकदमे में IPC की धारा 323, 504, 506, 452 के तहत केस दर्ज करवा दिया।

पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात से की है। बरौर थाना प्रभारी अमिता मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना पुलिस प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गई है, क्योंकि यह एक सुनियोजित वसूली के नेटवर्क का संकेत देती है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अन्य निर्दोष लोग भी इसी तरह की ठगी का शिकार बन सकते हैं।

शगुन महिला समूह की दोना-पत्तल इकाई का निरीक्षण

» संयुक्त मिशन निदेशक ने दीं आर्थिक सशक्तिकरण की टिप्स

» गौरीपुर गांव में महिला स्वावलंबन की मिसाल पेश कर रहा समूह

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (क्करररू) की संयुक्त मिशन निदेशक श्रीमती सुधा शुक्ला ने विकासखंड सरवनखेड़ा के ग्राम गौरीपुर में शगुन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित दोना-पत्तल निर्माण इकाई का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समूह की महिलाओं से संवाद कर उन्हें बेहतर आमदनी के लिए तकनीकी सुधार और व्यवसायिक मॉडल पर काम करने की सलाह दी।

निरीक्षण के दौरान मिशन निदेशक ने महिलाओं के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह इकाई ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने महिलाओं को उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने और बाजार से सीधा जुड़ाव करने पर ज़ोर दिया।

महादेव कुटी में महिला संकुल समिति का मूल्यांकन

रानी लक्ष्मीबाई प्रेरणा समिति के अभिलेखों का हुआ परीक्षण

गुणवत्ता सुधार हेतु अधिकारियों ने दिए दिशा-निर्देश

निरीक्षण के दूसरे चरण में श्रीमती सुधा शुक्ला ने ग्राम पंचायत फतेहपुर रोशनाई के ग्राम महादेव कुटी में संचालित ग्राम संगठन एवं क्लस्टर रायपुर क्षेत्र की रानी लक्ष्मीबाई प्रेरणा महिला संकुल समिति का भी निरीक्षण किया। इस दौरान समिति के अभिलेखों व संचालन व्यवस्था की जांच की गई।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी दस्तावेज अद्यतन और गुणवत्ता परख तरीके से बनाए जाएं। मौके पर डीसी एनआरएलएम श्री गंगाराम, एडीओ (आईएसबी) विमल सचान, जिला मिशन मैनेजर तौकीर आलम, ब्लॉक मिशन मैनेजर गरिमा सचान, सुमित सचान सहित कैडर की अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं।

सरवनखेड़ा की सैंथा ग्राम पंचायत में सीडीओ का औचक निरीक्षण

» संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जांची गई सफाई व्यवस्था

» मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन. ने प्रधान को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विकासखंड सरवनखेड़ा की ग्राम पंचायत सैंथा में मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन. ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत साफ-सफाई की व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। मौके पर परियोजना निदेशक वीरेन्द्र सिंह, एडीओ पंचायत वीरेन्द्र पाल, ग्राम सचिव सीमा पाल एवं ग्राम प्रधान मो. कासिम भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान सीडीओ को गांव में स्वच्छता व्यवस्था बेहद खराब मिली, जिस पर उन्होंने ग्राम प्रधान के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

स्वच्छता को प्राथमिकता देने के निर्देश, माइक्रो प्लान के तहत हो रहा अभियान

सीडीओ लक्ष्मी एन. ने कहा कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में माइक्रो प्लान के तहत चिकित्सा विभाग के सहयोग से संचारी रोगों की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसमें झाड़ी कटाई, पानी निकासी, शौचालयों की सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव जैसे कार्य शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वच्छता में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनुपस्थित अथवा उदासीन कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सभी जिम्मेदारों को अभियान को प्राथमिकता में रखकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

गजनेर पुलिस की मुस्तैदी से 5 घंटे में मिला गुमशुदा किशोर

» सीसीटीवी फुटेज से की गई तफ्तीश, हाईवे के पास मिला बच्चा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात, माती। गजनेर पुलिस ने एक बार फिर तत्परता की मिसाल पेश की। महज 5 घंटे में लापता 14 वर्षीय किशोर को ढूंढकर परिजनों को सौंप दिया गया। कीरतपुर निवासी अभिषेक पुत्र वीरेंद्र सिंह सुबह टहलने निकला था लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया।परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद गजनेर थाने में गुमशुदगी की सूचना दी। इस पर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने बिना समय गंवाए टीम के साथ फैक्ट्री एरिया और हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। जांच में किशोर को बारा टोल प्लाजा के पास देखा गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया।

थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही बच्चे को ढूंढना प्राथमिकता रही। गहनता से जांच करते हुए कुछ ही घंटों में सफलता मिल गई। परिजनों ने गजनेर पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर आभार व्यक्त किया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

विधायक के काफिले की 40 गाड़ियां टोल बिना जबरदस्ती निकलीं, जमकर हुआ हंगामा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बाराबंकी। लखनऊ-सुल्तानपुर हाईवे पर गोतौना गाँव के निकट पड़ने वाले टोल प्लाजा पर विधायक के समर्थकों ने बुधवार की सुबह जमकर हंगामा किया और बिना टोल दिए ही 40 गाड़ियां जबरदस्ती निकाल लीं गई।

उल्लेखनीय हैं कि लखनऊ- सुल्तानपुर हाईवे पर गोतौना गांव के पास पड़ने वाले बारा टोल प्लाजा पर बुधवार की सुबह 10 बजकर20 मिनट पर उस समय हंगामा हो गया, जब अपना दल (एस) के एक विधायक के काफिले में चल रही करीब 40 गाड़ियां टोल टैक्स दिए बिना टोल प्लाजा से पार करा दी गईं। इस घटना को देखने वाले लोगों के अनुसार टोलकर्मियों ने विधायक की गाड़ी को तो पहले निकाल दिया, लेकिन उसके बाद पीछे-पीछे आ रहे समर्थको के दर्जनों वाहनों को रोकने की कोशिश की। इसी को लेकर टोलकर्मियों और विधायक समर्थकों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हंगामे में बदल गई।

मौके पर तैनात पुलिस के गनर और समर्थकों ने मिलकर काफिले के सभी वाहनों को जबरन बैरियर हटवाकर टोल प्लाजा से पार कराया। विवाद बढ़ता देख स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को किसी तरह शांत कराया। टोल मैनेजर ने इस मामले में जहाँ कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं एनएचएआई के अधिकारियों के अलावा इसकी सूचना अपनी कंपनी के अधिकारियों को भेजी है। वहीं इस घटना को लेकर टोल कर्मचारियों में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि विधायक किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बनारस से लखनऊ की ओर जा रहे थे।

विद्यालय के सामने झूलता जर्जर बिजली तार, हादसे को दावत

» **विद्यालय में प्रतिदिन छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही सुरक्षा से खुला खिलवाड़ कर रही**

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बेलहरा (बाराबंकी)। उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहारी, पावर हाउस बेलहरा के ठीक सामने सड़क के ऊपर खतरनाक ढंग से झूलता जर्जर बिजली का तार कभी भी बड़ा हादसा करा सकता है।

विद्यालय में प्रतिदिन छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही बच्चों की सुरक्षा से खुला खिलवाड़ कर रही है।स्थानीय वार्डवासियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के लाइनमैन से तार को ठीक कराने की गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि लाइनमैन शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं।

सभासद नितिन वर्मा ने कहा कि विद्यालय के सामने इस तरह का जर्जर तार हादसे को न्योता दे रहा है। वहीं अनिल वर्मा, विवेक वर्मा, विनीत कुमार, विश्वनाथ और हरिओम ने बताया कि गांव में कई स्थानों पर बिजली की लाइनें इतनी नीचे लटक रही हैं कि कोई भी वाहन उनके संपर्क में आ सकता है।उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालय के सामने तार इतनी नीचे है कि यदि कोई बच्चा हाथ उठाए तो वह तार को छू सकता है।

बेलांव हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत चारों आरोपी बरी

» **15 साल बाद आया फैसला**

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जौनपुर। जिले के केराकत के बेलांव में हुए संजय निषाद व नंदलाल निषाद हत्याकांड में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत कुल चारों आरोपी बरी हो गए हैं।

अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व में चारों आरोपियों का बयान दर्ज हो गया था। बयान में सभी ने खुद को निर्दोष बताया था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने उन्हें राजनीतिक विद्वेषवश फंसाये जाने की बात कही थी। बता दें कि एक अप्रैल 2010 को 5.15 बजे सुबह बेलांव घाट बैरियर के पास टोल टैक्स के विवाद में संजय निषाद व नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

ये था आरोप-आरोप है कि ठेकेदारी की रंजिश

को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ ही आशुतोष सिंह, पुनीत सिंह व सुनीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिला किया। कोर्ट में गवाहों के बयान भी दर्ज हुए हैं। एडीजीसी लाल बहादुर पाल ने 20 गवाहों को परीक्षित कराया। बृहस्पतिवार को इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है।

अयोध्या में नकली डिग्री डिप्लोमा बनाने पर सीबीआई रेड

» गुलाबाड़ी में फर्जी डिग्री रैकेट का हुआ खुलासा, लाखों कैश और दस्तावेज बरामद

» बी फार्मा की फर्जी डिग्री बेचने वाले नेटवर्क पर देशभर में शिकंजा कस रही सीबीआइी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जांच में होगी अहम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। गुलाबाड़ी मोहल्ले में बुधवार सुबह अचानक केंद्रीय जांच ब्यूरो की एंटी करप्शन टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी बी फार्मा की फर्जी डिग्रियों से जुड़े एक बहुचर्चित मामले में की जा रही है, जिसकी कड़ियाँ दिल्ली से लेकर अयोध्या तक फैली हैं।

सीबीआई की टीम ने जिस मकान में दबिश दी, बृजरानी कुंज में रुदौली के प्राथमिक विद्यालय मरैचा में तैनात शिक्षक संतोष झा का मकान है। उनके पिता केशरी नंदन झा पुरातत्व विभाग के अधीन गुलाब बाड़ी में कार्यरत थे। उनके भाई मनोज झा ठेकेदारी के पेशे से जुड़े होने की चर्चा है। घर में मौजूद महिला शिक्षिका से गहन पूछताछ जारी है। टीम में सीबीआई के इंस्पेक्टर केके सिंह, एक महिला समेत चार लोग शामिल थे। लगभग नौ घंटे की जांच के बाद शाम चार बजे सीबीआई के इंस्पेक्टर ने नगर कोतवाली पुलिस को फोन करके बुलाया। इस बीच स्थानीय पुलिस बाहर खड़ी रही और अंदर सीबीआई की टीम जांच करती रही। रात 10 बजे तक जांच जारी रही। इस दौरान परिसर व आसपास के इलाकों में सन्नाटा छाया रहा।

सीबीआई को छानबीन में 15 लाख से अधिक कैश और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, जो इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने में अहम साबित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई देशभर में चल रही सीबीआई की उस मुहिम का हिस्सा है, जिसमें फर्जी डिग्री रैकेट के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य है।

स्थानीय लोगों के बीच सीबीआई की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। इस कार्रवाई के बाद अयोध्या में शिक्षा माफिया और भ्रष्टाचार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

सीबीआई सूत्रों के हवाले से

फर्जी बी फार्मा डिग्रियों के बदले लाखों में डील होती थी

दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी समेत कई राज्यों में फैला नेटवर्क

कई आरोपित पहले ही गिरफ्तार, अयोध्या में भी गिरफ्तारी संभव है।

यूपी कैबिनेट की बैठकः 30 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में आयोजित हुई बैठक

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे।उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की यह बैठक कई दूरगामी और जनहितकारी निर्णयों से भरपूर रही। रोजगार, बुनियादी ढांचा, न्यायिक सुधार और प्रशासनिक दक्षता से जुड़ी मंजूरियां इस बात का प्रमाण हैं कि योगी सरकार प्रदेश को विकास के नए शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जेपीएनआईसी की जिम्मेदारी अब एलडीए के पास

राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए जेपीएनआईसी (जेपी नेशनल इंटरनेशनल सेंटर) के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंप दी है। यह निर्णय केंद्र की सुविधाओं और संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

पूर्वांचल-आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा नया लिंक रोड

राज्य के कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करते हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले नए लिंक एक्सप्रेसवे को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे यातायात में तेजी आएगी और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।

बुंदेलखंड में औद्योगिक क्रांति की तैयारी

बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को स्वीकृति देकर सरकार ने क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को गति देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह निर्णय रोजगार और विकास दोनों के लिए वरदान साबित हो सकता है।

रोजगार और नियमावली सुधारों पर जोर

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को हरी झंडी मिल गई है, जिससे राज्य में युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर खुलेंगे।ग्राम विकास अधिकारी, वेटनरी फार्मासिस्ट, और उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावलियों में संशोधन तथा नई नियमावली लागू करने का फैसला लिया गया है।

भाषा संस्थान कर्मियों को बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि संस्थान की गुणवत्ता और निरंतरता बनाए रखने में भी सहायक होगा।

डिजिटल प्रशासन को मिलेगा नया आयाम

राज्य की समेकित वित्तीय प्रणाली (ढ्ढस्नस्न्र) को और अधिक सशक्त बनाने के लिए CDAC (Center for Development of Advanced Computing) को नामांकन के आधार पर जिम्मेदारी दी गई है। इससे सरकारी वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी।

कल लखनऊ में आम महोत्सव

» डीएम विशाख जी ने आम महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की

» सुरक्षा-यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश

» महोत्सव का उद्घाटन चार जुलाई को करेंगे सीएम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। आम महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के लिए डीएम विशाख जी व संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने बैठक की। डीएम ने सुरक्षा व यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

आम नागरिकों के लिए शहर के प्रमुख स्थलों से महोत्सव स्थल तक पर्याप्त मात्रा में बसें चलाने व उनकी सूची उपलब्ध कराने के लिए आरटीओ को निर्देशित किया। प्रदेश सरकार चार से छह जुलाई तक अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव का आयोजन कर रही है।

उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि महोत्सव का उद्घाटन

आम महोत्सव में लगभग 800 किस्मों के आमों का प्रदर्शन किया जाएगा

चार जुलाई को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

मुख्यमंत्री प्रदेश के आमों के कंटेनर को लंदन, दुबई सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए रवाना करेंगे।

वह स्मारिका का भी विमोचन करेंगे व प्रगतिशील आम उत्पादकों का सम्मान करेंगे। मंत्री ने कहा कि यह महोत्सव प्रदेश के आम उत्पादकों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने व आम के विविध स्वरूपों को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। डीएम ने सुरक्षा व यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

आम नागरिकों के लिए शहर के प्रमुख स्थलों से महोत्सव स्थल तक पर्याप्त मात्रा में बसें चलाने व उनकी सूची उपलब्ध कराने के लिए आरटीओ को निर्देशित किया।

उन्होंने बताया कि आम महोत्सव में लगभग 800 किस्मों के आमों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो प्रदेश की बागवानी विविधता से रूबरू कराएगा।

4 जुलाई को ही दोपहर 12 बजे से क्रेता-विक्रेता सम्मेलन तथा तकनीकी सत्रों में आम की सुरक्षित तुड़ाई, पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट, विपणन व निर्यात आदि पर चर्चा होगी।

शाम को आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

शाम छह बजे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ उद्यान विभाग के अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा करेंगे। इस अवसर पर प्रसिद्ध लोकगायक पवन सिंह की लोक प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण होंगी।

कुमार विश्वास की काव्य प्रस्तुति भी पांच जुलाई को सुबह 10 बजे तकनीकी सत्रों का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे। इस सत्र में आम उत्पादन तकनीक, पोषण प्रबंधन, कीट व व्याधि नियंत्रण, संरक्षित खेती जैसे विषयों पर वैज्ञानिकों एवं किसानों के बीच संवाद होगा।

इसी दिन दोपहर दो बजे बच्चों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता होगी, जो उत्सव में सहभागिता को और रोचक बनाएगी। शाम छह बजे आयोजित सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। इस अवसर पर कवि डॉ. कुमार विश्वास की काव्य प्रस्तुति होगी। छह जुलाई को सुबह 11 बजे से तकनीकी सत्र में आम प्रसंस्करण तकनीकों, विभागीय योजनाओं व वैज्ञानिक-उत्पादक परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर तीन बजे महोत्सव का समापन व पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। इसमें मुख्य अतिथि उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह होंगे।

यूपी में स्कूलों के मर्जर पर सियासी घमासान

» बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय ने इसके गलत बताया

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कम छात्रों वाले परिषदीय स्कूलों के विलय (मर्ज) का प्रस्ताव अब सियासी विवाद का रूप लेता जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर जहां शिक्षा जगत में चिंता जताई जा रही है वहीं अब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।

बसपा प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन/एकीकरण की आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने का जो फैसला लिया है वह गरीबों के करोड़ों बच्चों के लिए उनके घर के पास दी जाने वाली सस्ती व सुगम सरकारी शिक्षा के साथ अन्याय है। यह फैसला पहली नजर में ही

हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई याचिका

हाई कोर्ट इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित स्कूलों के मर्जर के खिलाफ याचिका दाखिल हुई। इसमें योगी सरकार पर सरकारी स्कूल बंद कर ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया जा रहा है।

अनुचित, गैर-जरूरी और गरीब-विरोधी प्रतीत होता है। मायावती ने साफ कहा कि सरकार को यह फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए ताकि गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके आसपास ही गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा मिलती रहे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो बसपा की सरकार बनने पर यह निर्णय रद्द किया जाएगा और प्रदेश में फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि सरकार गरीबों और आम जनता की शिक्षा के हित में इस पर

सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार जरूर करेगी।

इस मुद्दे पर सिर्फ बसपा ही नहीं बल्कि सपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्कूल मर्जर को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर आमादा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की नीतियां गरीबों और वंचितों को शिक्षा से वंचित करने की दिशा में काम कर रही हैं। सरकारी स्कूलों के विलय से ड्रॉपआउट रेट बढ़ेगा और लाखों बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे। सपा मुखिया ने योगी सरकार के इस फैसले पर कहा कि स्कूल मर्जर सोची समझी रणनीति है जिससे गरीबों को शिक्षा से दूर कर सके। सपा मुखिया ने कहा कि शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी शुरू हो जाएगी। आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है। यह सरकार हृदयहीन है जिसमें संवेदना न हो, वो सरकार नहीं चाहिए किसी को। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा शिक्षकों के साथ है जो बरसों से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जब कभी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा तो उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम हम हर हाल में करेंगे।

यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि स्कूलों को बंद करना शिक्षा के अधिकार (आरटीई) का खुला उल्लंघन है। विद्यालयों का विलय करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को निजी विद्यालयों को मान्यता देने के बजाय सार्वजनिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य का यह फैसला केवल बेरोजगारी को बढ़ाने और गरीबों को हाशिए पर धकेलने का काम करेगा। राय ने राज्यपाल से इस प्रस्तावित योजना पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है।

अमरनाथ यात्रा शुरू

पहले जत्थे ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है. 'बम-बम भोले' के जयकारों के बीच पहले जत्थे ने आज गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए और प्रात:कालीन आरती में हिस्सा लिया। शिवधाम में महादेव के जयकारे गूंजते रहे। आरती में श्रद्धा का सागर देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। 38 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है।

परमाणु बम पर आर-पार के मूड में ईरान

नई दिल्ली। ईरान पर अमेरिकी हमले के परमाणु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया। लेकिन अब विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये हमले ईरान को और खतरनाक रास्ते पर धकेल सकते हैं। ईरान अब न्यूक्लियर हथियार बनाने की राह पर गुपचुप तरीके से चल सकता है, क्योंकि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी संस्था आईएईए के साथ सहयोग खत्म करने का फैसला किया है।

$15 की पिन ने गिराया $200 मिलियन का ड्रीमलाइनर!

अहमदाबाद विमान हादसा : टेकऑफ के 38 सेकंड बाद ही हो गया था हादसा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अहमदाबाद। सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट 171 उड़ान भरने के महज 38 सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया और आग की लपटों में घिर गया। हादसे में 270 में से 269 लोगों की मौत हो गई थी। एकमात्र जीवित बचे यात्री ब्रिटिश नागरिक विवशकुमार रमेश (40) हैं, जिन्हें गंभीर जलन के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जांच एजेंसियों ने पुष्टि की है कि दुर्घटना का मुख्य कारण कप्तान की सीट में लगी एक छोटी धातु पिन का टूटना था, जिसे 1 जून को बदला गया था लेकिन उसके बाद ठीक से जांच नहीं की गई। उड़ान के 18वें सेकंड में पिन के टूटने से सीट पीछे खिसक गई और कप्तान सुमीत सभरवाल अनजाने में थ्रॉटल को आइडल पावर पर खींच लाए, जिससे दोनों इंजन की ताकत बंद हो गई। विमान केवल 650 फीट की ऊंचाई पर था और कुछ ही सेकंड में स्टॉल होकर नीचे गिर गया।

एफडीआर का विश्लेषण : इंजन, फ्लैप्स और एफएडीईसी सिस्टम सामान्य स्थिति में थे। थ्रॉटल आइडल पर आते ही थ्रस्ट खत्म, आरएएम एयर टर्बाइन (आरएटी) सक्रिय होना दर्शाता है कि पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी

विशेषज्ञ प्रतिक्रिया: हर पिन को अब क्रिटिकल मानना होगा : पूर्व एएआईबी के अधिकारी किशोर चिंता ने कहा, $15 के पुर्जे ने 270 लोगों की जान ले ली। यह पूरी इंडस्ट्री के लिए चेतावनी है। बोईंग 787 की प्रशिक्षक कैप्टन आयशा पटेल ने कहा कि 650 फीट की ऊंचाई पर कोई गलती माफनहीं होती। उपकरणों को और सुरक्षित बनाना होगा। इस त्रासदी ने 1988 की अलोआ एयरलाइंस की घटना की याद दिला दी, जहां एक छोटी सी मरम्मत से मिड-एयर डीकंप्रेशन हुआ था।

सरकारी और नियामकीय कार्रवाई: डीजीसीए ने 33 ड्रीमलाइनर की जांच के आदेश दिए, डीजीसीए प्रमुख विक्रम देव ने कहा, अब हर पिन और बोल्ट को भी क्रिटिकल पार्ट मानना होगा। फ्लाइट 171 की दुर्घटना बताती है कि विमानन सुरक्षा में हर पिन, हर स्क्रू की अपनी अहमियत होती है। यह त्रासदी महज एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि सुरक्षा संस्कृति पर सवाल है। यह चेतावनी है कि जांच में चूक किसी दिन जानलेवा साबित हो सकती है।

कंपनी में छंटनी

माइक्रोसॉफ्ट में बड़ा झटका, एक बार फिर बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा

एक झटके में 9100 कर्मचारियों को नौकरी गई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने फिर बड़ा फैसला लेते हुए करीब 9,100 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। यह 2023 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी है। कंपनी के टॉप अधिकारी जुडसन अल्थॉफ ने भी दो महीने की छुट्टी ली है।

दुनिया की जानी-मानी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर बड़ी छंटनी करने जा रही है। कंपनी ने बुधवार को पुष्टि की कि वह अपने 9,100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। यह कंपनी की 2023 के बाद से सबसे बड़ी छंटनी मानी जा रही है। इससे पहले मई और जून में भी माइक्रोसॉफ्ट ने हजारों कर्मचारियों की छंटनी की थी।

माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, यह छंटनी कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब 4 प्रतिशत हिस्सा है। फिलहाल दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के करीब 2.28 लाख कर्मचारी हैं। इसमें से कितने लोग अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित ऑफिस से हैं, इस पर कंपनी ने फिलहाल कोई साफ जानकारी नहीं दी है।

लगातार दूसरे महीने छंटनी : मई और जून में भी माइक्रोसॉफ्ट ने दो चरणों में छंटनी की थी। उस दौरान करीब 6,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसमें से 2,300 कर्मचारी वॉशिंगटन के बताए जा रहे हैं। अब जुलाई में एक बार फिर छंटनी से कंपनी के अंदर-बाहर बेचैनी बढ़ गई है।

क्या है छंटनी की वजह? : कंपनी ने कहा कि वह अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर कामकाज को ज्यादा प्रभावी बनाना चाहती है। बाजार में मंदी, लागत में कटौती और मुनाफे को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। टेक सेक्टर में पिछले कुछ समय से छंटनी का यह सिलसिला लगातार जारी है।

» 2023 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी छंटनी है

» टॉप अधिकारी जुडसन अल्थॉफ ने भी दो महीने की छुट्टी ली

» मई और जून में भी हजारों कर्मचारियों की छंटनी की

बड़े अधिकारी ने भी लिया ब्रेक : माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी जुडसन अल्थॉफ ने दो महीने के लिए छुट्टी (सैबेटिकल) पर जाने का फैसला लिया है। कंपनी ने बताया कि यह ब्रेक उन्होंने खुद लिया है, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के साथ जुड़ा हुआ है। अल्थॉफ सितंबर में अपनी टीम में वापस लौटेंगे।

सेल्स टीम पर भी असर : वहीं, माना जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की सेल्स टीम में भी आगे छंटनी देखने को मिल सकती है। यह विभाग कंपनी के लिए अहम है, लेकिन लागत कम करने के प्रयास में इसे भी प्रभावित किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की यह छंटनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में जारी वैश्विक संकट को और गहरा करती है। इससे पहले गूगल, अमेजन और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां भी इसी तरह हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ महीनों में यह सिलसिला जारी रह सकता है।